considered the feasibility of decontrolling the cloth ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH) : (a) Government is not proposing to lift completely the present control on cloth.

(b) Readjustment of control as may be necessary is under consideration of Government.

Integral Coach Factory

*1246. SHRI S. KUNDU : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether coaches built at the Integral Coach Factory have been found defective and need frequent repairs;

(b) whether a Railway Committee appointed for the purpose enquired into it in 1966 and pointed out several defects ; and

(c) if so, the steps which Government have taken to improve the condition of Railway coaches ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

अखबारी कागज का आयात

*1247. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि है भारत विदेशों से अखबारी कागज का आयात करता है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष विदेशों से कितने अखबारी कागज का आयात किया जाता है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है;

(ग) भारत में अखबारी कागज बनाने वाली प्रत्येक मिल की उत्पादन क्षमता कितनी है और वे मिलें किन-किन राज्यों में हैं; और

(घ) देश में अखबारी कागज की कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) 1966 में लगभग 1,07,000 मी० टन अखबारी कागज का आयात किया गया था जिसका मूल्य 11.78 करोड़ रुपये था और 1967-68 में लगभग 13 करोड़ रुपये के मूल्य का 1,20,000 मी० टन अखबारी कागज आयात किए जाने का अनुमान है ।

(ग) इस समय देश में अखबारी कागज बनाने का एक ही कारखाना है जो मध्य प्रदेश में है और उसकी वर्तमान वार्षिक क्षमता 30,000 मी० टन है ।

(घ) देश में अखबारी कागज की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है

(1) विद्यमान अखबारी कागज मिल की 30,000 मी० टन वार्षिक क्षमता 75,000 मी० टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाई जा रही है ।

(2) केरल में यूकिल्पटस के आधार पर अखबारी कागज बनाने के एक कारखाने को सरकारी क्षेत्र में केरल में स्थापित किए जाने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

(3) एक गैर-सरकारी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश सरकार से हिमालय क्षेत्र में नरम लकड़ी के आधार पर अखबारी कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने पर बातचीत कर रही है ।

(4) गैर-सरकारी पार्टियों को अखबारी कागज बनाने के कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहन देने के आशय से इस उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस प्राप्त करने वाले उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है ।

(5) देश में निर्मित अखबारी कागज पर उत्पादन शुल्क को हटा दिया गया है और अखबारी कागज बनाने के लिए आयतित लुग्दी से भी आयात कर हटा दिया गया है ।